



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2017/श्रावण 26, 1939

No. 319]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2017/SRAVANA 26, 1939

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 25 जुलाई, 2017

सं. टीएमपी/62/2009-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, पारादीप पत्तन न्यास के मौजूदा दरमान की वैधता का विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएमपी/62/2009-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

- (i). श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii). श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जुलाई, 2017 के 21 वें दिन पारित)

यह मामला पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के मौजूदा दरमानों (एसओआर) की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएमपी/62/2009-पीपीटी दिनांक 25 मार्च 2011 द्वारा पीपीटी का एसओआर अनुमोदित किया था जिसे 23 मई 2011 को राजपत्र सं. 111 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस आदेश ने दरमान की वैधता 31 मार्च 2013 निर्धारित की थी।

2.2. उसके बाद, प्रशुल्क में वेक्यूम से बचने और उक्त आदेश में उद्धरित कारणों से आवधिक अन्तरालों पर प्राधिकरण द्वारा एसओआर की वैधता विस्तारित की गई थी। अंतिम अवसर पर, प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएमपी/62/2009 दिनांक 4 जनवरी 2017 द्वारा पीपीटी के एसओआर की वैधता को 31 मार्च 2017 तक विस्तारित किया था जिसे 18 जनवरी 2017 को राजपत्र सं. 20 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। प्रत्येक अवसर पर वैधता विस्तार किए जाने के समय, पीपीटी को सलाह दी गई थी कि सामान्य संशोधन प्रस्ताव तत्काल दाखिल किया जाए।

2.3. पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 6 दिसम्बर 2016 द्वारा प्रशुल्क नीति 2015 का अनुसरण करते हुए अपने दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल किया था। इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया था और संदर्भित मामले पर 27 फरवरी 2017 को भुवनेश्वर में पीपीटी परिसर में संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी।

संयुक्त सुनवाई में उपयोक्ताओं एवं पीपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 3 मई 2017 द्वारा अपना संशोधित दरमान जमा किया है। पीपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव की प्राथमिक संवीक्षा के आधार पर, पीपीटी से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया है।

3. इसी बीच, पीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 30 जून 2017 द्वारा उल्लिखित किया है कि जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए तैयारी और लेखों के वार्षिक लेखापरीक्षा के कारण, अपेक्षित सूचना जमा करने में कुछ और समय लगेगा। वैसे, पीपीटी ने मौजूदा दरमान की वैधता को 30 सितम्बर 2017 तक विस्तारित करने पर विचार करने का अनुरोध किया था।

4. पीपीटी के एसओआर की वैधता 31 मार्च, 2017 को पहले ही समाप्त हो चुकी है। पीपीटी द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूचना/स्पष्टीकरण पर कार्यवाही करने के लिए अपेक्षित समय पर विचार करते हुए और पीपीटी के एसओआर में वेक्यूम से बचने के लिए, यह उपयुक्त महसूस किया गया है कि मौजूदा एसओआर की वैधता को 31 मार्च, 2017 तक विस्तारित कर दिया जाए, जैसाकि पीपीटी द्वारा अनुरोध किया गया है।

5. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह प्राधिकरण **पीपीटी के मौजूदा एसओआर की वैधता को 31 मार्च 2017 से परे बढ़ा कर 30 सितम्बर, 2017 तक** अथवा संशोधित एसओआर के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

टी. एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./184/17]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th July, 2017

No. TAMP/62/2009-PPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/62/2009-PPT

The Paradip Port Trust

QUORUM

Applicant

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 21st day of July, 2017)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates (SOR) of the Paradip Port Trust (PPT).

2.1. The Authority had approved the SOR of the PPT vide its Order No. TAMP/62/2009-PPT dated 25 March, 2011 which was notified in the Gazette of India on 23 May, 2011 vide Gazette no. 111. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March, 2013.

2.2. Thereafter, the validity of the SOR was extended by the Authority at periodic intervals to avoid a vacuum in tariff and for the reasons cited in the said Order. On the last occasion, the Authority had extended the validity of SOR of PPT upto 31 March, 2017 vide its Order No. TAMP/62/2009 dated 4 January, 2017 which was notified in the Gazette of India on 18 January, 2017 vide Gazette No. 20. While extending the validity at each occasion, the PPT was advised by the Authority to file the general revision proposal immediately.

2.3. The PPT has filed its proposal for general revision of its Scale of Rates, following Tariff Policy 2015 vide its letter dated 6 December, 2016. The proposal has been taken up on consultation and a joint hearing on the case in reference was held on 27 February, 2017 at the PPT premises in Bhubaneswar. Based on the request made by the users as well as PPT at the joint hearing, PPT vide its letter dated 3 May, 2017 has submitted its revised SOR. Based on a preliminary scrutiny of the proposal filed by PPT additional information/clarification has been sought from PPT.

3. In the meanwhile, the PPT vide its email dated 30 June 2017 has stated that due to Annual Audit of Accounts and preparedness for implementation of GST, it will take some more time for it to submit the requisite information. As such, PPT has requested to consider extension of the validity of existing SOR i.e. up to 30 September, 2017.

4. The validity of the SOR of PPT has already expired on 31 March, 2017. Considering the time required for processing the information/clarification to be furnished by the PPT and in order to avoid a vacuum in the SOR of PPT, it is felt appropriate to extend the validity of the existing SOR beyond 31 March, 2017, as requested by the PPT.

5. In view of the above, this Authority extends the validity of the existing SOR of PPT beyond 31 March, 2017 and up to 30 September, 2017 or till the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./184/17]